

न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 मुकाम भिनाय  
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./1/2022

1. देबीसिंह पुत्र स्व० बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर
2. सोरता पुत्री स्व० बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर
3. कैलाशी पुत्री स्व० बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर
4. गुड्डी पुत्री स्व० बालूराम जाति मीणा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-13.08.2022

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- धर्मवीर बामणियां

2. पैरोकार सरकार

प्रार्थी ने इस प्रार्थना-पत्र में सारांशः निवेदन किया है कि मौजा बनेड़िया पटवार मण्डल हियालियां भू० अभिलेख क्षेत्र एकलसिंहा तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता सं० 48 में दर्ज आराजी ख.न. 48 रकबा 0.24 है० एवं ख०न० 49 रकबा 0.20 कुल किता-2 कुल रकबा 0.44 है० भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज हो गयी है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीगण का सही जाति मीणा है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगणों की सही जाति दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षकारान को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा कथन किये गये कि संलग्न राजस्व जमाबन्दी अनुसार प्रकरण में पक्षकार पूर्ण नहीं है। प्रार्थीगणों द्वारा पत्रावली में वर्तमान जमाबन्दी एवं पहचान के दस्तावेजात संलग्न किये गये। प्रार्थीगणों द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज अथवा राजस्व जमाबन्दी संलग्न नहीं की गई हैं, जिससे साबित होता हो की राजस्व कार्मिकों के द्वारा भूलवश या अन्य लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति मीणा के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में वर्णित कथनों को दोहराते हुए, प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किये कि प्रार्थीगणों द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज अथवा पुराना राजस्व जमाबन्दी रिकॉर्ड संलग्न नहीं किया गया है, जिससे साबित होता हो की राजस्व कार्मिकों के द्वारा भूलवश या अन्य लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीगणों की जाति मीणा के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों

अध्यक्ष


लोक अदालत बैंच  
(त. नं. ... .. ति)

जिला-अजमेर

तथा राजस्व रिपोर्ट बाबत संलग्न राजस्व जमाबन्दी घान बनेदिया का अवलोकन किया। कहील प्राणी ऐसे कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, जिससे प्राणी-घर में बर्गित कर्जों की पुष्टि होती हो कि पूर्व में राजस्व जमाबन्दी में प्राणीयता की जाति भीमा अंकित थी, तथा बाद में किसी कारण-वश जाति रावल अंकित कर दी गई। राजस्व रिपोर्ट बाबत संलग्न राजस्व जमाबन्दी एवं कहील प्राणी एवं पैरोकार सरकार के लकी, जवाब के अवलोकन एवं मनन उपरान्त बैंच सदस्यों द्वारा प्राणीयता द्वारा प्रस्तुत बर्गित-घर अप्पारत घारा 136 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम अनुतोष योग्य ना होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद ताभील तकभील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(कविश) राणावत)  
 अध्यक्ष  
 रा10 लोक अदालत  
 लोक अदालत बैंच  
 (तातुका विधिक सेवा समिति)  
 कंकड़ी, जिला-अजमेर

  
 (प्रभात त्रिपाठी)  
 सदस्य  
 रा10 लोक अदालत